



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 21 अगस्त, 2001/30 भाद्रपद, 1923

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 21 अगस्त, 2001

संख्या 1-50/2001-वि० स०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2001 (2001 का

1960

असाधारण राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2001/30 भावण, 1923

विधेयक संख्यांक 14) जो आज दिनांक 21 अगस्त, 2001 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है । सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

अजय भण्डारी,
सचिव ।

2001 का विधेयक संख्यांक 14.

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2001

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2001 है। संक्षिप्त नाम।

2. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मूल अधिनियम' कहा गया है) को धारा 8 में, द्वितीय परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :— धारा 8 का संशोधन।

“परन्तु यह और कि ग्राम सभा क्षेत्र के भाग या पूर्ण का प्रतिनिधित्व करने वाला पंचायत समिति का सदस्य, सम्बद्ध ग्राम पंचायत(तों) का भी सदस्य होगा और उसे मत देने का अधिकार होगा।”।

3. मूल अधिनियम की धारा 11 में,—

धारा 11
का संशोधन।

(क) उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(1) ग्राम पंचायत, अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट कृत्यों का पालन करेगी।”;
और

(ख) उप-धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(2) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा ग्राम पंचायत को, अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट उन मामलों सहित आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं को तैयार करने और निष्पादन का कार्य सौंप सकेगी, तथा ग्राम पंचायत उन कृत्यों का पालन भी करेगी।”।

4. मूल अधिनियम की धारा 23 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, धारा 23 का प्रतिस्थापन।
अर्थात् :—

“23. स्थाई समितियों का गठन और कृत्य.—(1) प्रत्येक ग्राम पंचायत, निर्वाचन द्वारा इसके सदस्यों में से निम्नलिखित स्थाई समितियां गठित करेगी :—

(i) प्रधान के नेतृत्व में, ग्रामीण सड़कों और सार्वजनिक भवनों से सम्बन्धित कृत्यों का पालन करने के लिए, लोक निर्माण समिति, तथा उप-प्रधान भी इस समिति का सदस्य होगा ;

- (ii) प्रधान के नेतृत्व में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा, महिलाओं, बालकों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से सम्बन्धित कृत्यों का पालन करने के लिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सलाहकार समिति ;
- (iii) प्रधान के नेतृत्व में, शिक्षा से सम्बन्धित कृत्यों का पालन करने के लिए, ग्राम शिक्षा समिति ;
- (iv) प्रधान के नेतृत्व में, वनरोपण, भूमि संरक्षण, दावानल नियंत्रण से सम्बन्धित कृत्यों का पालन करने के लिए, वन समिति ;
- (v) उप-प्रधान के नेतृत्व में, कृषि/बागवानी उत्पादन, पशुपालन से सम्बन्धित कृत्यों का पालन करने के लिए, कृषि उत्पादन समिति ;
- (vi) उप-प्रधान के नेतृत्व में, मिर्चार्ड और जन स्वास्थ्य से सम्बन्धित कृत्यों का पालन करने के लिए, मिर्चार्ड एवं जन स्वास्थ्य समिति ; और
- (vii) उप-प्रधान के नेतृत्व में, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता समिति ।

(2) प्रत्येक समिति में ग्राम पंचायत से, यथास्थिति, प्रधान या उप-प्रधान सहित, दो से कम और तीन से अधिक सदस्य नहीं होंगे :

परन्तु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सलाहकार समिति तथा वन समिति में, सहयोजित सदस्यों को मिलाकर कम से कम तीन महिला सदस्य होंगी :

परन्तु यह और कि यदि उप-प्रधान, ग्राम पंचायत के प्रधान के रूप में कार्य करता है तो उप-धारा (1) के खण्ड (v), (vi) और (vii) में वर्णित स्थाई समिति के सदस्य, अपने में से इनके अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे ।

- (3) प्रत्येक समिति, कृषक क्लब, महिला मण्डल, युवक मण्डल, सहकारी सोसाइटी और सम्बद्ध विभागों के सदस्यों को ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए, सहयोजित करेंगी । सहयोजित सदस्यों के अधिकार और दायित्व ऐसे होंगे जैसे विहित किए जाएं :

परन्तु प्रत्येक स्थाई समिति, ग्राम सभा से दो सदस्यों से अनधिक भी, जिन्हें उस विषय, जिसके लिए उक्त समिति गठित की गई है, की जानकारी हो, सहयोजित करेंगी :

परन्तु यह और कि एक ही व्यक्ति, दो से अधिक स्थाई समितियों के लिए सहयोजित नहीं हो सकेगा :

परन्तु यह और कि प्रत्येक समिति में सहयोजित सदस्यों सहित, पांच से कम नहीं और 20 से अधिक सदस्य होंगे ।

(4) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, ग्राम शिक्षा समिति, यही होगी जिसी हिमाचल प्रदेश अधिनियम प्राथमिक शिक्षा नियम, 2000 के अधीन, प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा अधिमूर्चित की गई है।

(5) स्थानीय समितियां उप-धारा (1) के अधीन ऐसे कृत्यों का पालन करेंगी जो ग्राम पंचायत द्वारा उन्हें सौंपे जाते हैं।”।

5. मूल अधिनियम की धारा 78 की उप-धारा (1) में खण्ड (ब) में, परन्तु के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

धारा 78
का संशोधन।

“(क) धारा का प्रतिनिधित्व करने वाला जिला परिषद् का सदस्य, जिसमें पंचायत समिति क्षेत्र पूर्णतः या भागतः समाविष्ट है।”।

6. मूल अधिनियम की धारा 118 में, उप-धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तु के जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

धारा 118
का संशोधन।

“परन्तु राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, निदेशक, यदि आवश्यक समझे, निजी प्राधिकरणों/व्यक्तियों को भी, जो संपरीक्षा में विशेषज्ञ हों, संदाय के आधार पर संपरीक्षा के संचालन के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।”

7. मूल अधिनियम की धारा 161 में,—

धारा 161
का संशोधन।

(क) खण्ड (ii) में, “जिला परिषद्” शब्दों के पश्चात् और “के मामले में” शब्दों से पूर्व, “के सदस्यों” शब्द जोड़े जाएंगे; और

(ख) खण्ड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“(iii) जिला परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मामले में, प्रायुक्त द्वारा।”।

8. मूल अधिनियम की धारा 174 की उप-धारा (1) में,—

धारा 174
का संशोधन।

(क) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ख) सभी या किसी निर्वाचित व्यक्ति के निर्वाचन को शून्य घोषित करने; या” ; और

(ख) ऐसे प्रतिस्थापित किए गए खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड (ग) जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“(ग) सभी या किसी निर्वाचित व्यक्ति के निर्वाचन को अवैध घोषित करने और यात्री या किसी अन्य अभ्यर्थी को मध्यक रूप से निर्वाचित किए जाने, का आदेश करेगा।”।

9. मूल अधिनियम की धारा 175 में,—

धारा 175
का संशोधन।

(क) विद्यमान शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“निर्वाचन का शून्य घोषित करने के आधार।” ;

(ख) उप-धारा (1) में, "निर्वाचित व्यक्ति के निर्वाचन को अपास्त कर देगा" शब्दों के स्थान पर, "निर्वाचित व्यक्तियों के निर्वाचन को शून्य घोषित कर देगा" शब्द रखे जाएंगे; और

(ग) उप-धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(2) धारा 175-क के उपबन्धों के अधीन, जब उप-धारा (1) के अधीन निर्वाचित व्यक्ति का निर्वाचन शून्य घोषित किया जा चुका हो, तब इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन, नया निर्वाचन कराया जाएगा।"

धारा 175-क और 175-ख का अंतःस्थापन।

10. मूल अधिनियम की धारा 175 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"175-क. निर्वाचित व्यक्ति से भिन्न अभ्यर्थी जिन आधारों पर निर्वाचित घोषित किया जा सकेगा वे आधार—यदि ऐसे किसी व्यक्ति ने, जिसने याचिका दाखिल की है निर्वाचित व्यक्ति के निर्वाचन को प्रश्नगत करने के अतिरिक्त इस घोषणा के लिए दावा किया है कि वह स्वयं या कोई अन्य अभ्यर्थी सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गया है और प्राधिकृत अधिकारी की यह राय है कि—

(क) याची को या ऐसे अन्य अभ्यर्थी को विधिमाम्य मतों की बहुसंख्या वास्तव में प्राप्त हुई है, अथवा

(ख) निर्वाचित व्यक्ति को भ्रष्ट आचरण द्वारा, अभिप्राप्त मतों के अभाव में याची या ऐसे अन्य अभ्यर्थी को विधिमाम्य मतों की बहुसंख्या अभिप्राप्त हुई होती,

तो प्राधिकृत अधिकारी निर्वाचित व्यक्ति के निर्वाचन को शून्य घोषित करने के पश्चात् यह घोषणा करेगा कि, यथास्थिति, याची या ऐसा अन्य अभ्यर्थी सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गया है।

175-ख. मतों के बराबर होने की दशा में प्रक्रिया.—यदि निर्वाचन याचिका के विचारण के दौरान यह प्रतीत होता है कि निर्वाचन में किन्हीं अभ्यर्थियों के बीच मत बराबर हैं और मतों में एक मत के जोड़ देने से उन अभ्यर्थियों में से कोई निर्वाचित घोषित किए जाने का हकदार हो जाएगा, तो—

(क) रिटनिंग अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किया गया कोई विनिश्चय वहां तक, जहां तक कि उन अभ्यर्थियों के बीच प्रश्न का अवधारण करता है, उस याचिका के प्रयोजनों के लिए भी प्रभावी होगा; और

(ख) जहां तक कि वह प्रश्न ऐसे विनिश्चय द्वारा अवधारित नहीं हुआ है, वहां प्राधिकृत अधिकारी उन के बीच लाट द्वारा विनिश्चय करेगा और ऐसे अग्रसर होगा मानो जिम किसी के पक्ष में लाट निकल आए उसे एक अतिरिक्त मत प्राप्त हुआ था।"

धारा 181 का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 181 में, विद्यमान खण्डों (i) और (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(i) उप-मण्डल अधिकारी द्वारा पारित आदेश की दशा में, उपायुक्त को, और इस खण्ड के अधीन पारित उसका आदेश अंतिम होगा;

- (ii) उपायुक्त द्वारा पारित मूल आदेश की दशा में, वित्तायुक्त (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार को; और
- (iii) आयुक्त द्वारा आदेश पारित किए जाने की दशा में, वित्तायुक्त (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार को,

अपील कर सकेगा और वह अपील की सुनवाई करेगा तथा 90 दिन के भीतर उसका निपटारा करेगा, और अपील पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।”।

12. मूल अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची-1 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

अनुसूची-1
का प्रति-
स्थापन।

अनुसूची-1

[धारा 11 (1) देखें]

ग्राम पंचायत के कृत्य

1. स्वच्छता, सफाई और न्यूमेन्स का निवारण और उसका उपशमन ;
2. सार्वजनिक कुओं, तालाबों और टैंकों तथा परम्परागत पारम्परिक जल के स्रोतों का सन्निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण ;
3. ग्राम पथों, खच्चरों के लिए सड़कों और ग्रामीण सड़कों, पुलियों, पुलों और बांधों, जो लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित तथा पोषित न हों, का सन्निर्माण और अनुरक्षण ;
4. सार्वजनिक मार्गों, शौचालयों, नालियों, टैंकों, कुओं तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों का सन्निर्माण, अनुरक्षण और इनको सफाई ;
5. भवनों, शौचालयों, मूत्रालयों, नालियों तथा फलन शौचालयों के सन्निर्माण का विनियमन ;
6. कचरा इकट्ठा करना और जलन करना तथा कचरा क्षेपण के लिए स्थानों का पृथक् रक्षण ;
7. उपयोग न किए जाने वाले कुओं, अस्वच्छ तालाबों, पोखरों, खाइयों तथा गड्डों को भरना और सीढ़ीदार कुओं (बावड़ीयों) को स्वच्छ कुओं में परिवर्तित करना ;
8. ग्राम मार्गों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था करना ;
9. सार्वजनिक मार्गों या स्थानों और उन स्थलों में, जो निजी सम्पत्ति न हों या जो सार्वजनिक उपयोग के लिए खुले हों, चाहे ऐसे स्थल पंचायत में निहित हों या राज्य सरकार के हों, बाधाओं तथा आगे निकले हुए भाग को हटाना ;
10. सार्वजनिक भूमि का प्रबन्ध और ग्राम पंचायत में निहित या उसके नियन्त्रणाधीन ग्राम स्थल, चारागाहों तथा अन्य भूमियों का प्रबन्ध और विकास ;
11. संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन, राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए से भिन्न, प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारकों का अनुरक्षण ;
12. ग्राम पंचायत की सम्पत्ति का अनुरक्षण ;
13. वृक्षारोपण तथा पंचायत वनों का संरक्षण ;
14. शवों, पशु-शवों और अन्य घृणोत्पादक पदार्थों के व्ययन के लिए स्थानों का विनियमन ;
15. लावारिस शवों और पशु शवों का व्ययन ;
16. मांस के विक्रय तथा परीक्षण का विनियमन ;
17. कांजी-हाउस की स्थापना और प्रबन्ध तथा पशुओं से संबंधित अभिलेखों का रखा जाना ;
18. बाजारों और मेलों की स्थापना, प्रबन्ध तथा विनियमन ;
19. जन्म, मृत्यु और विवाहों के अभिलेखों का रखा जाना।”

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के विद्यमान उपबन्धों के अनुसार, जिला परिषद् और पंचायत समितियों के सदस्य, क्रमशः पंचायत समिति तथा पंचायतों की बैठकों में भाग नहीं ले सकते हैं, और यह देखा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं के उच्च स्तर के सदस्यों की पंचायतों की निम्न स्तर द्वारा सामान्यतः उपेक्षा की जाती तथा पंचायतों की निम्न स्तर की बैठकों में सक्रिय भाग नहीं ले सकते हैं। अतः यह विनिश्चय किया गया है कि जिला परिषदों और पंचायत समितियों के सदस्य मत-विवेकार सहित क्रमशः पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के भी सदस्य बनाए जा सकेंगे।

वर्तमान में पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट ग्राम पंचायतों के कृत्य बाध्यकर स्वरूप के हैं। ग्राम पंचायतों को जवाबदेय और उत्तरदायी बनाने के लिए अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट कृत्यों में से कुछ को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

यह देखा गया है कि विभिन्न विभाग, अपने विभागों से सम्बन्धित पर्यवेक्षी कृत्यों का पालन करने के प्रयोजन हेतु ग्रामीण स्तर की समितियों का गठन कर रहे हैं। इन समितियों में, अन्य सदस्यों के साथ-साथ, ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधि भी हो सकेंगे। तथापि, विभिन्न विभागों द्वारा ऐसी ग्रामीण/पंचायत स्तर समितियों के गठन के परिणामस्वरूप, ग्रामीण स्तर पर समितियों की विविधता (बहुलता) हो रही है, क्योंकि पूर्वोक्त उपबन्धों के अनुसार ग्राम पंचायतों की स्थाई समितियाँ गठित हैं। यह स्थानीय लोगों में भ्रम उत्पन्न कर रही है तथा विभाग और ग्राम पंचायतों की समितियों के बीच भी थोड़ा ही समन्वय है। इस लिए यह विनिश्चय किया गया है कि विभिन्न विभाग उनके विभागीय कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने और उनका संप्रेक्षण करने के लिए, पृथक् समितियाँ बनाने के बजाए, ग्राम पंचायतों की स्थाई समितियों के साथ उनकी समितियों को समाकलित करें। तदनुसार, पूर्वोक्त अधिनियम में, इस प्रभाव का उपबन्ध बनाया जा रहा है।

वर्तमान में, पंचायतों के लेखों की संपरीक्षा, पंचायती राज विभाग के संपरीक्षा अभिकरण (ऐजेन्सी) द्वारा की जाती है। यहां ऐसी भी कतिपय योजनाएँ हैं जो भारत सरकार द्वारा मंचित की जाती हैं, जिनके विषय में विशिष्ट मार्गदर्शी सिद्धान्त हैं जिनके अधीन, निजी अभिकरणों, जो ऐसे क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं के माध्यम से संपरीक्षा संचालित की जानी अपेक्षित है। इसलिए, निदेशक, पंचायती राज को, पंचायतों की संपरीक्षा का संचालन करने हेतु संपरीक्षा में विशेषज्ञ निजी अभिकरणों/व्यक्तियों को प्राधिकृत करने को सशक्त करने का विनिश्चय किया गया है।

तत्समय, जिला परिषद् के पदाधिकारियों की दशा में, निर्वाचन अर्जियाँ उपायुक्त द्वारा सुनी जाती हैं। जबकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन भी, जिला परिषद् की बैठक में, उपायुक्त की अध्यक्षता के अधीन किया जाता है। अतः यह समुचित समझा गया है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की दशा में, निर्वाचन अर्जी, आयुक्त द्वारा सुनी जा सकेगी और निर्वाचन अर्जी पर आयुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील, वित्तायुक्त राजस्व हिमाचल प्रदेश सरकार को की जाएगी। इसी प्रकार निर्वाचन अर्जी पर, उपायुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील भी, वित्तायुक्त (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार को की जाएगी।

विद्यमान उपबन्ध के अनुसार निर्वाचन अर्जियाँ या तो खारिज की जाती हैं या निर्वाचित व्यक्ति का निर्वाचित अशास्त किया जाता है। चूँकि, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अनुसार, निर्वाचन अर्जियाँ या तो खारिज की जाती हैं अथवा सभी या किसी निर्वाचित व्यक्तियों का निर्वाचन शून्य घोषित किया जाता है तथा याची या किसी अन्य अभ्यर्थी को सम्यक् रूप से निर्वाचित हुआ घोषित किया जाता है। अतः पूर्वोक्त अधिनियम के उपबन्धों को, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अनुरूप लाने के लिए, अधिनियम में उचित उपबन्ध बनाने का विनिश्चय किया गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

शिमला :

तारीख : अगस्त, 2001।

प्रकाश चौधरी,
प्रभारी मन्त्री।

वित्तीय जापन

—अन्य—

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी जापन

विधेयक का खण्ड 4, राज्य सरकार को, ग्राम पंचायतों की स्थाई समितियों द्वारा मदस्यों के सञ्चय और ऐसे सहयोजित सदस्यों के अधिकारों और दायित्वों को भी विनिश्चित करने के विषय में नियम बनाने के लिए सशक्त करता है। शक्तियों का यह प्रत्यायोजन अनिवार्य एवं सामान्य स्वरूप का है।

1968

असाधारण राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2001/30 भावण, 1923

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2001

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

प्रकाश चौधरी,
प्रभारी मन्त्री।

रामेश्वर शर्मा,
सचिव (विधि)।

शिमला :
तारीख : अगस्त, 2001.

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 14 of 2001.

THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) BILL, 2001.

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A
BILL

further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (4 of 1994).

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-second Year of the Republic of India, as follows:—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Amendment) Act, 2001.

Short title.

2. In section 8 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (hereinafter referred to as the 'principal Act'), after the second proviso, the following shall be added, namely:—

Amendment of section 8.

"Provided further that the member of the Panchayat Samiti, representing a part or whole of the Gram Sabha area shall also be the member of the concerned Gram Panchayat(s) and shall have the right to vote."

3. In section 11 of the principal Act,—

Amendment of section 11.

(a) for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:—

"(1) The Gram Panchayat shall perform the functions specified in Schedule-I."; and

(b) in sub-section (2), for the words and sign "specified in Schedule-II", the words and sign "including those matters specified in Schedule-II and the Gram Panchayat shall perform such functions" shall be substituted.

4. For section 23 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

Substitution of section 23.

"23. *Constitution and functions of Standing Committees.*—(1) Every Gram Panchayat shall from amongst its members constitute by election, following Standing Committees:—

- (i) Public Works Committee for performing functions relating to rural roads and public buildings to be headed by the Pradhan and the Up-Pradhan shall be the member of this committee;
- (ii) Health and Family Welfare Advisory Committee for performing functions relating to Health and Family Welfare

Department, welfare of women, children, Scheduled Castes and Scheduled Tribes to be headed by the Pradhan ;

- (iii) Village Education Committee for performing functions relating to education to be headed by the Pradhan ;
- (iv) Forest Committee for performing functions relating to afforestation, soil conservation, prevention of forest fire to be headed by the Pradhan ;
- (v) Agriculture Production Committee for performing functions relating to Agriculture/Horticulture production, Animal Husbandry to be headed by the Up-Pradhan ;
- (vi) Irrigation and Public Health Committee for performing functions relating to Irrigation and Public Health to be headed by the Up-Pradhan ;
- (vii) Food, Civil Supply and Consumers Committee to be headed by Up-Pradhan.

(2) Each Committee shall consist of not less than two and not more than three members from Gram Panchayat including the Pradhan or the Up-Pradhan, as the case may be :

Provided that the Health and Family Welfare Advisory Committee and Forest Committee shall have at least three women members including co-opted members :

Provided further that if the Up-Pradhan acts as the Pradhan of the Gram Panchayat, the members of the Standing Committees mentioned in clauses (v), (vi) and (vii) of sub-section (1) shall elect its Chairman from amongst themselves .

(3) Each Committee shall co-opt, in such manner as may be prescribed, members of Farmers Club, Mahila Mandals, Yuvak Mandals, Co-operative Societies and the concerned departments. The rights and liabilities of the co-opted members shall be such as may be prescribed :

Provided that each Standing Committee shall also co-opt not more than two members from Gram Sabha having knowledge of the subject for which the said committee had been constituted :

Provided further that the same person may not be co-opted for more than two Standing Committees :

Provided further that each committee shall consist of not less than five and not more than twenty members including the co-opted members.

(4) Notwithstanding anything contained in this section, the Village Education Committee shall be the same as notified by the Primary Education Department under the Himachal Pradesh Compulsory Primary Education Rules, 2000.

(5) The Standing Committees shall perform such functions under sub-section (1) as are entrusted to them by the Gram Panchayat."

5. In section 78 of the principal Act, in sub-section (1), after proviso to clause (d), the following shall be added, namely :— Amendment of section 78.
 - “(e) the member of the Zila Parishad, representing the ward which comprises wholly or partly the Panchayat Samiti area.”.
6. In section 118 of the principal Act, after sub-section (2), the following proviso shall be added, namely :— Amendment of section 118.

“Provided that the Director may, with the prior approval of the State Government, also authorise private agencies/persons, who are specialised in audit to conduct audit, on payment basis, if considered essential”.
7. In section 161 of the principal Act :— Amendment of section 161.
 - (a) in clause (ii), after the words “in the case of”, the words “members of” shall be added; and
 - (b) after clause (ii), the following shall be added, namely :—
 - “(iii) in the case of Chairman and Vice-Chairman of Zila Parishad, by the Commissioner.”.
8. In section 174 of the principal Act, in sub-section (1), — Amendment of section 174.
 - (a) for clause (b), the following shall be substituted, namely :—
 - “(b) declaring the election of all or any of the elected persons to be void ; or” ; and
 - (b) after clause (b) so substituted, the following clause (c) shall be added, namely :—
 - “(c) declaring the election of all or any of the elected persons to be void and the petitioner or any other candidate to have been duly elected.”.
9. In section 175 of the principal Act,— Amendment of section 175.
 - (a) for the existing heading, the following shall be substituted, namely :—

“Grounds for declaring elections to be void.”;
 - (b) in sub-section (1), for the words “set aside the election of the elected person”, the words “declare the election of the elected persons to be void” shall be substituted ; and
 - (c) for sub-section (2), the following shall be substituted, namely :—
 - “(2) Subject to the provisions of section 175-A, when an election of an elected person has been declared to be void under sub-section (1), a fresh election shall be held under the provisions of this Act and the rules made thereunder.”.

Insertion of
sections 175-
A and 175-
B.

10. After section 175 of the principal Act, the following shall be inserted, namely:—

“175-A. **Grounds for which a candidate other than the elected person may be declared to have been elected.**—If any person who has lodged a petition has, in addition to calling in question the election of the elected person, claimed a declaration that he himself or any other candidate has been duly elected and the authorised officer is of opinion,—

- (a) that in fact the petitioner or such other candidate received a majority of valid votes; or
- (b) that but for the votes obtained by the elected person by corrupt practices, the petitioner or such other candidate would have obtained a majority of the valid votes,

the authorised officer shall after declaring the election of the elected person to be void declare the petitioner or such other candidate, as the case may be, to have been duly elected.

175-B. **Procedure in case of equality of votes.**—If during the trial of an election petition, it appears that there is an equality of votes between any candidates at the election and that the addition of a vote would entitle any of those candidates to be declared elected, then—

- (a) any decision made by the returning officer under the provisions of this Act shall, in so far as it determines the question between those candidates, be effective also for the purposes of the petition; and
- (b) in so far as that question is not determined by such a decision, the authorised officer shall decide between them by lot and proceed as if the one on whom the lot then falls had received an additional vote.”.

Amendment
of section
181.

11. In section 181 of the principal Act, for the existing clauses (i) and (ii), the following shall be substituted, namely:—

- “(i) in case the order is passed by the Sub-Divisional Officer, to the Deputy Commissioner and his orders passed under this clause shall be final ;
- (ii) in case the original order is passed by the Deputy Commissioner, to the Financial Commissioner (Revenue) to the Government of Himachal Pradesh ; and
- (iii) in case the order is passed by the Commissioner, to the Financial Commissioner (Revenue) to the Government of Himachal Pradesh,

and he shall hear and dispose of the appeal within a period of 90 days whose decision shall be final.”.

12. For Schedule-I appended to the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

Substitution
of Schedule
-1.

“SCHEDULE-I

[See section 11 (1)]

FUNCTIONS OF GRAM PANCHAYATS

1. sanitation, conservancy and prevention and abatement of nuisance;
2. construction, repair and maintenance of public wells, ponds, tanks and conventional/traditional sources of water;
3. construction and maintenance of village paths, mule roads and rural roads, culverts, bridges and bunds which are not constructed or maintained by the Public Works Departments;
4. construction, maintenance and cleaning of public streets, latrines, drains, tanks, wells and other public places;
5. regulating the construction of buildings, latrines, urinals, drains and water closets;
6. collection and disposal of refuse and earmarking places for dumping of refuse;
7. filling of disused wells, in sanitary ponds, pools, ditches and pits and conversion of step wells into sanitary wells;
8. lighting of village streets and other public places;
9. removing of obstructions and projections in public streets or places and in sites not being private property or which are open to use of public, whether such sites are vested in the Panchayat or belong to the State Government;
10. management of public land and management and development of village site, grazing lands and other lands vested in or under the control of the Gram Panchayat;
11. maintenance of ancient and historical monuments other than those declared by or under law made by Parliament to be of national importance;
12. maintenance of Gram Panchayat property;
13. plantation and preservation of Panchayat Forests;
14. regulating places for disposal of dead bodies, carcasses and other offensive matters;
15. disposal of unclaimed corpses and carcasses;
16. regulation of sale and preservation of meat;
17. establishment and management of cattle ponds and maintenance of records relating to cattle;
18. establishment, management and regulation of markets and fairs; and
19. maintenance of records of births, deaths and marriages.”.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

As per the existing provisions of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994, members of Zila Parishads and Panchayat Samitis cannot take part in the meetings of the Panchayat Samitis and Gram Panchayats respectively and it has been noticed that the members of the higher tier of the Panchayati Raj Institutions are generally ignored by the lower tiers of the Panchayats and cannot take active part in the meetings of the lower tier of the Panchayats. Hence it has been decided that the members of the Zila Parishads and members of the Panchayat Samitis may also be made the members of the Panchayat Samitis and Gram Panchayats respectively with right to vote.

At present the functions of the Gram Panchayats as specified in Schedule-I to the Act *ibid* are obligatory in nature. In order to make the Gram Panchayats accountable and responsible, some of the functions specified in Schedule-I should be made mandatory.

It has been seen that various departments for the purpose of performing supervisory functions concerning their departments have been constituting village level committees. These committees may among other members also have the elected representatives of the Gram Panchayats. However, as a result of constitution of such village/Panchayat level committees by various departments, there is a multiplicity of committees coming up at the village level because as per the existing provisions of the Act *ibid* there are constituted the standing committees of the Gram Panchayats. This is creating confusion amongst local people and there is also little co-ordination between the committees of the department and the Gram Panchayats. It is, therefore, decided that different departments instead of forming separate committees for implementing and overseeing their departmental programmes should integrate their committees with the Standing Committees of the Gram Panchayats. Accordingly a provision to this effect is being made in the Act *ibid*.

At present the audit of accounts of Panchayats is performed by the audit agency of the Panchayati Raj Department. There are certain schemes which are funded by Government of India regarding which there are specific guidelines under which the audit is required to be conducted through private agencies who are specialized in such field. Therefore, it has been decided to empower the Director of Panchayati Raj to authorise private agencies/persons specialised in audit to conduct the audit of Panchayats.

Presently the election petitions in the case of office bearers of Zila Parishad are heard by the Deputy Commissioner. Whereas, the elections of Chairman and Vice-Chairman is also held in the meeting of Zila Parishad, under the presidentship of Deputy Commissioner. Thus, it has been felt appropriate that the election petition in the case of Chairman or Vice-Chairman may be heard by the Commissioner and the appeal against the order of the Commissioner on election petition should lie to the Financial Commissioner (Revenue) to the Government of Himachal Pradesh. Similarly in the case of appeal against the orders of the Deputy Commissioner on election petition shall also lie to the Financial Commissioner (Revenue) to the Government of Himachal Pradesh.

As per the existing provisions the election petitions are either dismissed or the election of the elected person has to be set-aside. Since, as per provision of the Representation of the People Act, 1951, the election petition are either to be dismissed or the election of all or any of the elected person is declared to be void and the petitioner or any other candidate is declared to have been duly elected. Thus, in order to bring the provisions of the Act *ibid* in consonance with the provisions of Representation of Peoples Act, 1951, it has been decided to make suitable provisions in the Act.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

PRAKASH CHAUDHARY,
Minister-in-Charge.

SHIMLA :

the August, 2001.

FINANCIAL MEMORANDUM

-NIL-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 4 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules regarding co-optation of members by Standing Committees of the Gram Panchayats and also for determining the rights and liabilities of such co-opted members. This delegation of powers is essential and normal in character.

1976

असाधारण राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अगस्त, 2001/30 श्रावण, 1923

**THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) BILL,
2001**

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (4 of 1994).

PRAKASH CHAUDHARY,
Minster-in-Charge.

RAMESHWAR SHARMA,
Secretary (Law).

SHIMEA :
The August, 2001.